IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

''भारत सरकार के ऋण–प्राप्तियों का वि"लेशण''

डॉ0 आलोक सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर
वाणिज्य संकाय,
श्री गणे"ा राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
डोभी, जौनपुर(यू0पी0)

सार :–
प्रजातान्त्रिक भाासन व्यवस्था में जब से लोक–कल्याण कारी राज्यों का विकास हुआ है, जिससे ऋणों का महत्व बढ़ने लगा है। विकास के लिए आन्तरिक एवं वाह्य ऋण लेने की प्रवृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऋण भारतीय बजट प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो बजटीय व्यय को संतुलीत करती है। भारत एक विकास"ाील दे"ा है और विकास के पथ पर अग्रसरित है जिसको अपने विकास के लिए अधिक से अधिक वित्तीय संसाधनों की जरूरत है इन वित्तीय संसाधनो में ऋण एक अहम वित्तीय साधन है। भारत सरकार द्वारा यदि ऋण का प्रयोग सावधानी से किया जाता है तो यह दे"ा के विकास मे अहम भूमिका आदा करता है लेकिल यदि इसका प्रयोग अच्छी प्रकार से नही किया गया तो विकास की गति को बाधित कर सकता है। ऋण का किसी भी दे"ा के अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पडता है । यदि ऋण को निर्धारित मापदण्ड के तहत प्रयोग किया जाय तो यह दे"ा के आर्थिक विकास ही नही रोजगार, औद्योगिक विकास, कृशि आदि के विकास को प्रोत्साहित करता है और यहि मापदण्ड के अनुसार ऋण का प्रयोग नही किया जाता है तो यह इन्हे हत्तोसहित भी करता है।

प्रस्तावना :–
सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा प्राप्त किये गये ऋण होते है। यह सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत्र है विगत कुछ वर्शो में यह भारतीय वित्त व्यवस्था का एक एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। भारत सरकार अपने सार्वजनिक ऋण आर्थात लोक ऋण में केवल उन वित्तीय देनदारियो को भामिल करती है जो भारत के समेंकित निधि की भावी प्राप्तियों की गारंटी पर ली गई हो तथा इस निधि से देय हों। इस प्रकार परिभाशित लोक ऋण मे बाजार उधार भामिल रहते है। दे"ा के भीतर से लिए गये उधारो को आन्तरिक ऋण तथा दे"ा के बाहर से लिया गया ऋण को बाह्य .ऋण या विदे"ाी ऋण कहा जाता है।

भारत सरकार के ऋण का स्रोत:–

वर्तमान भारतीय बजेटरी व्यवस्था के अनुसार भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के अर्न्तगत तीन प्रकार के ऋण आते है–1–आन्तरिक ऋण 2–विदे"ाी ऋण एवं 3–अन्य ऋण, आन्तरिक एवं विदे"ाी ऋण भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण के अर्न्तगत आते है और इसका भ्गतान सामेकित कोश के अर्न्तगत सुरक्षित होता है जबकि अन्य ऋण सार्वजनिक खाते में दिखायी जाती है एवं सामेंकित कोश के अर्न्तगत सुरक्षित नही होती है। भारतीय संविधान की धारा 293 के अर्न्तगत संसद सार्वजनिक ऋण की सीमा निधारित कर सकती है।[1]

भारत में सार्वजनिक ऋण का औचित्य:–

सार्वजनिक ऋण के संदर्भ में एक प्र"न उठता है कि सरकार द्वारा उधार लेना कहाँ तक उचित है? सरकार को किन मजबूरियों में उधार लेन आव"यक हो सकता है तथा किन अन्य परिस्थितियों में वह इसका नीति भाास्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती है आदि। भारत सरकार के ऋणों का औचित्य को निम्न बिन्दुओं से दिखाया जा सकता है[2]–

1–संतुलित बजटीय नीति का अनुसण करते हुए भी सरकार की प्राप्तियों और अदायगियों में अल्पावधिक असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे उधार लेना पड़ सकता है

2–युऋ, प्राकृतिक आपत्तियाँ आदि सरकार के व्यय में अनपेक्षित बढोतरी लाने का कारण बन सकते है तथा सरकार को उधार लेना पड़ सकता है।

3–आधुनिक आर्थिक चितंन में सरकार की बजटीय नीतियो का एक अग्रणीय स्थान है। अधिकतर सरकारों का भी मत है कि उन्हे लोक कल्याण और अर्थव्यवस्था के विकास में एक सकिय भूमिका निभनी चाहिए। इन उद्दे"यों की प्राप्ति हेतु इतने अधिक साधनों की आव"यकता पड़ती है कि अधिकतर सरकारों की कर–राजस्व तथा अन्य कर–भिन्न प्राप्तियाँ अप्रर्याप्त है तथा उन्हे उधार लेना पड़ता है। यह बात वि"ोशकर अवसंचनात्मक सुविधाओं को मुहैया करने तथा अन्य प्रकार से पूँजी निर्माण के मामलों में लागू हाती है। इ स प्रकार की गतिविधियों से लोक ऋण के भुगतान के लिए कर–राजस्व में दीर्धकालीन वृद्धि की आ"ाा की जा सकती है। परंतु कल्याणकारी योजनाओं पर किए गए व्यय से भविश्य में राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होना आव"यक नही है, केवल इसकी सम्भांवना मात्र है।

4–लोक ऋण के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि इ सके माध्यम से एक विकास"ाील अर्थव्यवस्था की मुद्रा औ साखकी बढ़ती आव"यकता की पूर्ति होती है। इस प्रकार को अर्थव्यवस्था की मुद्रा और साख की आव"यकता दो कारणों से लगातर बढती रहती है, अर्थात (क)– अर्थव्यवस्था के विकास के साथ इसकी बढ़ती गतिविधियों का वित्त–पोशण, तथा (ख)–कय– विकय और उधार की गतिविधियों के बढते अनुपात का मौद्रीकरण। क्योकि मुद्रा एवे साख अंततः सरकारी करेंसी तथा उधार पर निर्भर करत है, अतः यह आव"यक है कि विकास की प्रकिया को सुदृढता प्रदान करने के लिए सरकार सार्वजनिक ऋण में बढ़ोतरी करे।

सार्वजनिक ऋण की सीमा :–

यहाँ पर एक बुनियादी प्र"न यह उठतार है की क्या एक सामान्य सरकार अपनी इच्छानुसार असीमित उधार ले सकती है? क्या इसके देय–ऋण की संचित मात्रा की कोई सीमा है? इस प्र"न के पीछे एक सत्य यह भी है कि पिछले कुछ द"ाकों में भारत सरकार सहित अनेक सरकारों के ऋण में चिंताजनक तीव्रता से वृद्धि हुई है तथा कुछ सरकारे ऋण के फन्दे में फस चुकी है अर्थात उन्हे अपने पहले के ऋण के ब्याज तथा मूल के भूगतान हेतू भी नए ऋण लेने की आव"यकता पड़ती है।

लेक ऋण की सीमा का पहला प्रतिबन्ध यह है कि प्रति वर्श नये उधार की रा"ि मे हो रही वृद्धि है। प्रतिवर्श उधार में निवल वृद्धि हो सकती है, उधार की सकल परि"ुद्ध देय रा"ि हो सकती है अथवा ऋण की सकल रा"ि/राश्ट्रीय उत्पाद का एक अनुपात हो सकती है। इसी प्रकार ऐसे एक अथवा एक से अधिक अर्थो में सीमा का निर्धारण किसी कानून अथवा सरकार द्वारा स्वयं ही अपनाए गये किसी संकल्प के अनुसरण में हो सकता है।

एक आधुनिक सरकार को अपने ऋण नीति को तय करते हुए, कानूनी प्रतिबन्धनों एवं स्वमंयम के अतिरिक्त, सार्वजनिक ऋण की अत्यधिक बढ़ोतरी से सरकार की बजटीय नम्यता घटती है। ऋण के ब्याज तथा मूलधन की बढती अदायगी–रा"ियों के कारण सरकार की अन्य बजटीय मदों पर व्यय करने की क्षमता घट जाती है।

लोक ऋण की अधिकता से निजी निवे"ा पर कई प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पडने का डर रहता है। प्रथम, निजी निव"ा के लिए उधार लेने के स्रोत भुाश्क होने लगते है। द्वितीय, ब्याज की दर में वृद्धि के कारण न केवल उत्पादन लागत बढती है, प्रत्युत मुद्रस्फीति का दबाव भी बढ जाता है। इससे दे"ा के भीतर वितरणीय असमानताओं में वृद्धि के अतिरिक्त व्यापार संतुलन बिगड सकता है। तृतीय, सरकार के लोक ऋण में केन्द्रीय बैक से लिए गए उधार के अनुपात की अधिकता होने से उपरोक्त दुश्परिणामों की तीव्रता और भी बढ जाती है।

दीर्घकाल मे आर्थिक विकास के साथ–साथ उपरोक्त संभावित परिणाम सं"ोधनीय हो सकते है। इस प्र"न का उत्तर कि सार्वजनिक ऋण की सर्वोपयुक्त रा"ि क्या है? काफी हद तक राश्ट्रीय आय के आकार पर निर्भर करता है। राश्ट्रीय आय मे बढोतरी के साथ–साथ अर्थव्यवस्था की वित्त पोशण की आव"यकता बढती ह। परन्तु वित्त उपलब्धि का अंतिम आधार सार्वजनिक ऋण होता है, अतः आर्थि विकास के साथ–साथ सार्वजनिक ऋण की इश्टतम मात्रा भी बढती जाती है। जब सरकार अपनी ऋण नीति को काफी नियंत्रित एवं सुचारू रूप संचालन करें, उधार लेने में संयम और सावधानी बरते, और इसे केवल प्राथमिकता वाली मदों पर व्यय करने का प्रयत्न करे तो सार्वजनिक ऋण दे"ा एवं अर्थव्यवस्था के लिए हितकर होती है। सार्वजनिक ऋण को कानूनी तौर पर सीमाबद्ध करने के पक्ष में एक सक्षम तर्क यह है कि अधिकतर सरकारों में अपने व्यय को अनुचित स्तर तक तीव्रता से बढाने की सहज पवृत्ति होती है यदि इस प्रवृत्ति पर अंकु"ा न लगाया जाए ता एक सामान्य सरकार ऋण लेकर भी इस प्रवृत्ति की तुश्टि करने की चेश्टा करती है। इस मामले मं इसके विवेक पर भारोसा करना खतरें से खाली नही है।

सार्वजनिक ऋण और आर्थिक विकास :– आर्थिक विकास एक बहुआयामी और जटिल प्रकिया है। इसमें एक सुसंगठित लोक ऋण नीति की महत्वपूर्ण योगदान होता है। परन्तु ऐसी ऋण नीति की संरचना और उसके कार्यान्वयन मं अनेको कठिनाइयाँ आती है। आर्थिक विकास के साथ मुद्रा और सख की आव"यता भी बढती है, जिसके दो कारण है–आर्थिक गतिविधि में बढोतरी तथा उनमें मुद्राकृत गतिविधियों के अनुपात में दीर्घकालीन वृद्धि होता है। अर्थव्यवस्था में वित्तीय लेन–देन के सभी करार करेंसी की मात्राओं में होने के कारण सरकार की वित्तीय देयताओं म वृद्धि किए बिना उपरोक्त बढती आव"यकता की पूर्ति नही की जा सकती। करेंसी समस्त वित्तीय ढाँचे की बुनियाद का काम करती है तथा सामान्यतः करेन्सी की प्रचलीत मात्रा बढाने के लिए सरकार को उधार लेना पडता है। यह भी स्मरणीय है कि यदि सरकार उधार लेने मे लापरवाहि बरते अथवा ऋण रा"ियों को उपभोग व्यय–मदों पर लगा दे तो अर्थव्यवस्था का वित्तीय ढाँचा लाभान्वित होने के स्थान पर क्षतिग्रस्त हो सकता है।

प्रत्येक अर्थव्यवस्था को अपनी उत्पादन क्षमता बनाये रखने के लिए बचत एवं निवे"ा की आव"यकता होती है। एक अल्पविकसित दे"ा की यह आव"यकता और भी अधिक होती है परन्तु ऐसी अर्थव्यवस्था को बचत और पूंजी निर्माण में सामान्य से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पडता है। प्रतिव्यक्ति आय के कम होने के कारण तथा गरीब लोगो की संख्या अधिक होने के कारण इसकी बचत क्षमता अति कम होती है इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार से कुछ प्रभावी कदमों की अपेक्षा की जाती है। सरकार यदि अपनी राजस्व प्राप्तियों में से समुचित बचत ओर पूंजी निवे"ा करने में असमर्थ हो तो उधार लेकर उन मदों पर व्यय कर सकती है जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बचत निवे"ा तथा अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता मे वृद्धि करते है।

सार्वजनिक ऋण अर्थव्यवस्था के निवे"ा संसाधनों का विकासोन्मुख पुनराबटंन एवं आर्थिक विकास में सहायक हो सकता है। ध्यानयोग्य बात यह है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक उधार की प्राप्तियों का उपयोग व्यय एव अन्य अनुत्पादक मदों पर लगा देने पर आर्थिक विकास के प्रोत्साहित होने की आ"ाा नही की जा सकती परन्तु सार्वजनिक उधार से लोक कल्याण की योजनाओ के वित्त पोशण की नीति विवादास्पद है। एक मतानुसार लोक कल्याण के वित्त पोशण के लिए सरकार के उधार लेकर नही, बल्कि कर तथा कर भिन्न राजस्व में बढोत्तरी तथा अपने अनाव"यक व्यय मे कटौती द्वारा साधन जुटाने चाहिए।

भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का वि"लेशणः–

(भारत सरकार की ऋण प्राप्तियाँ स.घ.उ. के प्रति"ात के रूप मे)

(तालिका –क)

(₹करोड़ मे)

वित्तीय वर्ष	स.घ.उ.	ऋण प्राप्तियाँ	प्रतिशत
2012–13 वास्त.	10028118	541230	5.39712437
2013–14 वास्त.	11355073	522029	4.59731963
2014–15 वास्त.	12653762	432973	3.42169388
2015–16 वास्त.	13567192	532782	3.92698799
2016–17 वास्त.	15075429	535619	3.55292708
2017–18 वास्त.	16784679	591062	3.52143762
2018–19 वास्त.	18840731	649418	3.44688324
2019–20 सं.अ.	21100607	766846	3.63423668
2020–21 ब.अ.	22489420	797337	3.54538712

(स्रोत–भारत सरकार का बजट दस्तावेज–प्राप्ति बजट में पूंजी प्राप्तियाँ (2012–13 से 2020–21तक)

सकल घरेलू उत्पाद 2012–13 से 2020–21 तक के बजट सार के संसोधित अनुमान से)

किसी भी दे"ा की सरकार को मनमाने ढ़ग से ऋण लेने की छूट नही होती है यदि ऋण लेने की सीमाओं का उल्लघन किया जाय तो इसका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। भारत सरकार की ऋण प्राप्तियों की तुलना तालिका–क से की जाय तो स्पश्ट होता है की भारत सरकार का ऋण वित्तीय वर्श 2012–13 में 541230 करोड रूपया था जो 2020–21 के बजट अनुमान में बढकर 797337 करोड रूपया हो गया इस तहर से देखते है कि भारत सरकार का ऋण वर्श दर वर्श वढ रहा है। इसका मतलब यह हुआ की बजट राजस्व में ऋण की भूमिका वर्श दर वर्श महत्वपूर्ण रहा ह। भारत द्वारा लिए जाने वाले ऋण मे वाह्य ऋण की मात्रा में भी लगातर वृद्धि की प्रवृत्ति रही है जिससे हमारा वह्य दायित्व भी लागातर बढ रहा है तथा वह्य निर्भरता भी बढता जा रहा। जो एक विकास"ाील अर्थव्यवस्था के लिए सही नही। भारत सरकार को बजट घाटे को कम करना चाहिए और ऋण की निर्भरता भी कम करनी चाहिए।

भारत सरकार के ऋण राजस्व की तुलना सकल घरलू उत्पाद से की जाय तो स्पश्ट होता है कि वित्तीय वर्श 2012–13 में ऋण की मात्रा सकल घरेलू उत्पाद के 5.39 प्रति"ात था जो 2020–21 के बजट अनुमान में घट कर 3.54 प्रति"ात हो गया है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में ऋण की मात्रा अद्यापि कम हुई है फिर भी यह सकल घरेलू उत्पाद का लग–भग 4 प्रति"ात बना हुआ है जो दे"ा तथा अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नही है। भारत सरकार की ऋण लेने की प्रवृत्ति मे वृद्धि हुई है। इसे नियन्त्रित किया जाना चाहिए नही तो यह हमारी दे"ा एवं अर्थव्यवस्था के लिए हितकर नही है।

वर्तमान समय मे भारता सरकार का बढता ऋण भार बजट के लिए हितकर नही है क्योकि बजट का अधिकां"ा भाग ऋण एवं उसके ब्याज का भुगतान करने में चला जा रहा है तथा विकास के लिए प्रर्याप्त धनरा"ि बजट के माध्यम से आवण्टि नही हो पा रहा है। अतः भारत सरकार को ऋण लेने की प्रवृत्ति में सुधार करना चाहिए।

निश्कर्श :– ऋण घाटें की वित्त व्यवस्था का बजट में एक उपयोगी साधन है। जब सरकार का व्यय, आय से अधिक होता है तो इसे घाटे की वित्त व्यवस्था कहा जाता है। सरकार को इस आधिक्य व्यय को पूरा करने के बहुत से साधन होते है जिसमें ऋण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ऋण आन्तरिक एवं वाह्य दो प्रकार के होते है। ऋण सरकार का एक दायित्व होता है जैसे–जैसे ऋण की मात्रा बढती जाती है वैसे–वैसे सरकार का दायित्व भी बढता जाता है। जब ऋण का भूगतान किया जात है तो मूलधन के अलावा ब्याज का भी भूगतान भी करना होता है। ऋण की रा"ि आव"यकता से अधिक हो जाता है तो बजट आय का अधिकां"ा भाग ऋण एवं ब्याज के भूगतान में चला जात है जिससे दे"ा के विकास के लिए उपलब्ध राजस्व की मात्रा कम हो जाती है और दे"ा का वास्तविक विकास नही हो पाता है।

ऋण के सम्बन्ध में उपरोक्त किये गये वि"लेशण से स्पश्ट है कि यदि ऋण का प्रयोग नियन्त्रित रूप से किया जाय तो यह दे"ा के विकास को आगे ले जा सकता है तथा इसे अनियन्त्रित रूप से प्रयोग किया गया तो यह दे"ा के विकास को पिछडा भी सकता है। अतः सरकार को ऋण साधन का प्रयोग नियन्त्रित रूप से करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1––प्रो0 एस.एन लाल–'मुद्र, बैकिंग तथा लोक वित्त 2009' पेज. नं.–241, ि"ाव पब्लि"िाग हाउस इलहाबाद

2–डॉ0 एच0एल0 भाटिया–लोक वित्त पेज0 नं0 174